

## न्यायालय जिला कलक्टर, झुझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी  
आई.ए.एस.

अपील संख्या 32/2022

1. मु0 बाला उर्फ बिमला पुत्री कानिया उर्फ कन्हैयालाल पत्नि नौरंगलाल, जाति मेघवाल, निवासी दूदवा, तहसील सूरजगढ, जिला झुझुनू ( राज0 ) हाल निवासी मटाणा, तहसील चिडावा, जिला झुझुनू।
2. मु0 संतोष पुत्री कानिया उर्फ कन्हैयालाल पत्नि मनोहरलाल, जाति मेघवाल, निवासी दूदवा, तहसील सूरजगढ, जिला झुझुनू ( राज0 ) हाल निवासी मटाणा, तहसील चिडावा, जिला झुझुनू।  
---अपीलान्ट्स

बनाम

1. बिमला देवी पत्नि अन्तर सिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम कुहाड, तहसील व जिला झुझुनू ( राज0 )।
2. सुबेसिंह पुत्र धर्मवीर सिंह, जाति जाट, निवासी दूदी, तहसील सूरजगढ जिला झुझुनू (राज)।
3. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पिलानी, तहसील सूरजगढ, जिला झुझुनू जरिये शाखा प्रबंधक।

---रेस्पोडेन्ट्स

प्रथम अपील अ0धा0 75 राज भू राजस्व अधि0 1956 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय तहसीलदार ( भू-अभिलेख ) सूरजगढ, जिला झुझुनू ( राज0 ) बाबत नामान्तरकरण सं0 1440 ग्राम दुदवा, तहसील सूरजगढ जमीन खसरा नं0 374 आदेश दिनांक 22.05.2022

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट- अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री अशोक लाम्बा, एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 व 2 की ओर से उपस्थित।

### आदेश

दिनांक 09.11.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार ( भू-अभिलेख ) सूरजगढ के आदेश दिनांक 22.05.2022 नामान्तरकरण संख्या 1440 ख0न0 374 वाके ग्राम दूदवा के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 96 जा0दी0 एवं प्रा0प0 अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र दफा 96 जा0दी0 एवं प्रा0प0 अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट्स निम्न है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर बहस बाबत नामान्तरकरण सं0 1440 ग्राम दूदवा खिलाफ कानून है। आदेश जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। अदालत मातहत ने राजस्थान रिकॉर्ड्स रूल्स 1957 व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में नामान्तरकरण से सम्बन्धित जो प्रावधान है उनको नजर अंदाज कर रेस्पोडेन्ट सं0 2 के हक में उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। विधि में यह व्यवस्था है कि सम्पूर्ण हिस्से का बेचान नहीं होने की सूरत में भौतिक कब्जे की जांच किया जाना आवश्यक है और कब्जे का मानचित्र नामान्तरकरण की पुश्त पर बनाया जाना भी आवश्यक है। विवादित आराजी पर आदेश जैर बहस पारित होने के रोज तथा पहले व विक्रय पत्र निष्पादित व पंजीबद्ध होने के रोज पहले व वर्तमान में रेस्पोडेन्ट का भौतिक कब्जा नहीं रहा है। कब्जे के बिन्दू की जांच किये गये अदालत मातहत नें रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 2 के हक में करवाये गये बेचान के आधार पर नामान्तरकरण जैर बहस स्वीकार किया है। जमीन जैर बहस का बेचान गलत रिकॉर्ड के आधार पर बिना कब्जे के हुआ है। जमीन जैर बहस के सम्बन्ध में राजस्व अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ की अदालत में बेचान की कार्यवाही होने के पहले से अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट सं0 1 के मध्य राजस्व वाद लम्बित है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट को रही है। उक्त राजस्व वाद की जानकारी अदालत मातहत को भी रही है। वास्तविक रूप से जमीन जैर बहस अनुसूचित जाति की खातेदारी की

है और अदालत मातहत ने उक्त तमाम तथ्यों की जानकारी होते हुये भी रेस्पोजेन्ट सं० 2 के हक में नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। जमीन जैर बहस अपीलान्ट्स के कब्जे काश्त व खातेदारी की है। खातेदारी हककों एवं बेचान के पहले से कर रखा है। उक्त तथ्य की जानकारी पटवारी हल्का, भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार ( भू अभिलेख ) सूरजगढ को रही है। जमीन जैर बहस के गत खसरा नं० 213/2 रहे है जो पहले अपीलान्ट्स की माता की खातेदारी में रही है। इस प्रकार अपीलान्ट्स आदेश जैर बहस से प्रभावित है और प्रभावित पक्षकार की हैसियत से यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। इजाजत हेतु दफा 96 का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। रेस्पोजेन्ट सं० 1 ने गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर जमीन जैर बहस का बेचान दिनांक 19.06.2020 को रेस्पोजेन्ट सं० 2 के सगे भाई बिजेन्द्र सिंह व मुंशीराम पुत्र दरियासिंह, जाति जाट, निवासी लाडुन्दा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं के हक में किया। उक्त बेचान बिना कब्जे व बिना प्रतिफल के हुये। रेस्पोजेन्ट संख्या 2 के भाई बिजेन्द्र सिंह के हक मे नामान्तरकरण संख्या 1251 दिनांक 25.06.2020 को स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध अपीलान्ट्स द्वारा अदालत हाजा के यहा एक अपील उनवानी मु० बाला वगै० बनाम बिमला देवी वगै० अपील संख्या 175/2020 प्रस्तुत की गई जो अपील अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 12.08.2021 के द्वारा स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 1251 ग्राम दूदवा दिनांक 25.06.2020 को निरस्त किया गया और अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ को यह निर्देश दिये गये कि उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ की अदालत मे विचाराधीन वाद संख्या 178/2009 मे निर्णय के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करे। अदालत हाजा द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना के कम मे नामान्तरकरण संख्या 1251 को अदालत मातहत ने नामान्तरकरण संख्या 1357 दिनांक 10.09.2021 ग्राम दूदवा के द्वारा खारीज कर दिया। अदालत मातहत ने रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 19.06.2020 को अवैध राजस्व रिकार्ड के आधार पर मुंशीराम के हक मे हुए बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1327 ग्राम दूदवा दिनांक 08.04.2021 को स्वीकार किया और उक्त नामान्तरकरण संख्या 1327 ग्राम दूदवा को आदेश दिनांक 13.06.2021 के द्वारा रिव्यू कर निरस्त कर दिया और अदालत मातहत ने उक्त रिव्यू आदेश मे यह फाईडिंग दी कि जमीन जैर बहस अनुसूचित जाति की खातेदारी की है और उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ की अदालत मे प्रकरण लम्बित है। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने जानबूझकर बदनीयती से रेस्पोजेन्ट संख्या 2 से षडयन्त्र कर उपर वर्णित तमाम तथ्यों को छिपाकर गलत रिकार्ड के आधार पर 1/2 हिस्से की भूमि का बेचान दिनांक 23.03.2022 को रेस्पोजेन्ट संख्या 2 के हक मे कर दिया और उक्त बेचान के आधार पर दिनांक 20.05.2022 को अदालत मातहत ने रेस्पोजेन्ट संख्या 2 के हक मे नामान्तरकरण संख्या 1440 ग्राम दूदवा स्वीकृत कर दिया। पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक तथा तहसीलदार सूरजगढ ने अपने पदीय कर्तव्य का दुरुपयोग कर नामान्तरकरण संख्या 1327 ग्राम दूदवा आदेश दिनांक 10.06.2021 मे दर्ज फाईडिंग को नजर अंदाज कर उक्त नामान्तरकरण संख्या 1440 साजसी रूप से रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 को फायदा पहुंचाने की नीयत से स्वीकार किया है। पटवारी हल्का दूदवा तथा भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त पीपली व तहसीलदार सूरजगढ को उक्त तथ्य की बखूबी जानकारी रही है कि नामान्तरकरण संख्या 1440 ग्राम दूदवा मे उल्लेखित भूमि खसरा नम्बर 374 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की खातेदारी की भूमि रही है और उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे गलत रूप से दर्ज खातेदार रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने जमीन का बेचान दिनांक 19.06.2020 को रेस्पोजेन्ट सं० 2 के भाई बिजेन्द्र सिंह व मुंशीराम नामक व्यक्ति को कर दिया है। जिनके हक मे कमशः नामान्तरकरण संख्या 1251 ग्राम दूदवा दिनांक 25.06.2020 व नामान्तरकरण संख्या 1327 ग्राम दूदवा दिनांक 08.04.2021 को स्वीकृत हो चुके है और उक्त दोनो नामान्तरकरण कमशः आदेश दिनांक 10.09.2021 व दिनांक 10.06.2021 के निरस्त किये जा चुके है। इसके बावजूद भी अवैध व शून्य बेचान के आधार पर राजस्व वाद लम्बित रहने के दौरान अदालत मातहत ने नामान्तरकरण जैर बहस स्वीकार किया है। राजस्व वाद की अदालत मातहत को जानकारी रही है। विधि मे यह व्यवस्था है कि राजस्व वाद लम्बित रहने के दौरान नामान्तरकरण की कार्यवाही किसी अन्य व्यक्ति के हक मे नही करनी चाहिए। विधि मे यह भी व्यवस्था है कि गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर हुए बेचान के आधार पर कंता के हक मे नामान्तरकरण स्वीकार नही करना चाहिए। इस प्रकार अदालत मातहत ने अपने पद का दुरुपयोग कर जान बूझकर अवैधानिक कृत्य किया है। उपरोक्त अवैध राजस्व रिकार्ड व लम्बित दावा तथा पूर्व मे हुए बेचान एवं स्वीकृत हुए नामान्तरकरण तथा निरस्त हुए नामान्तरकरण आदेशों की जानकारी रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 को रही है। और इसके बावजूद भी रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने बिना हक अधिकार के रेस्पोजेन्ट संख्या 2 के हक मे बेचाननामा निष्पादित व पंजीबृद्ध करवाया है और बाला-बाला रूप से रेस्पोजेन्ट संख्या 2 ने अपने हक मे नामान्तरकरण जैर बहस स्वीकार करवाकर अपीलान्ट व रेस्पोजेन्ट

संख्या 3 को नुकसान कारित करने के उद्देश्य से रेस्पोजेन्ट संख्या 3 से ऋण प्राप्त कर रेस्पोजेन्ट संख्या 3 के नाम रहन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1443 दिनांक 25.05.2022 को स्वीकार करवा है जो कि एक अपराध है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। अपीलान्ट्स का वाद विषय वस्तु से संबंध है। इस तथ्य की जानकारी अदालत मातहत को आदेश जैर बहस पारित होने के रोज रही है। अपीलान्ट्स के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं हुई है। अदालत मातहत ने नामान्तरकरण संख्या 1327 ग्राम दूदवा रिव्यू आदेश दिनांक 10.06.2021 में दी गई फाइलिंग को नजर अंदाज कर उसके विपरीत निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अदालत मातहत ने विधि की अवहेला कर अपने पद का दुरुपयोग किया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2022 बाबत नामान्तरकरण सं० 1440 ग्राम दूदवा, तहसील सूरजगढ जमीन खसरा नं० 374 को अपास्त किये जाने का आदेश दिया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर बहस बाबत नामान्तरकरण सं० 1440 ग्राम दूदवा खिलाफ कानून है। आदेश जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। अदालत मातहत ने राजस्थान रिकॉर्ड्स रूल्स 1957 व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में नामान्तरकरण से सम्बन्धित जो प्रावधान है उनको नजर अंदाज कर रेस्पोजेन्ट सं० 2 के हक में उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। विधि में यह व्यवस्था है कि सम्पूर्ण हिस्से का बेचान नहीं होने की सूरत में भौतिक कब्जे की जांच किया जाना आवश्यक है और कब्जे का मानचित्र नामान्तरकरण की पुश्त पर बनाया जाना भी आवश्यक है। विवादित आराजी पर आदेश जैर बहस पारित होने के रोज तथा पहले व विक्रय पत्र निष्पादित व पंजीबद्ध होने के रोज तथा पहले व वर्तमान में रेस्पोजेन्ट का भौतिक कब्जा नहीं रहा है। कब्जे के बिन्दू की जांच किये बिना ही अदालत मातहत ने रेस्पोजेन्ट सं० 1 द्वारा रेस्पोजेन्ट सं० 2 के हक में करवाये गये बेचान के आधार पर नामान्तरकरण जैर बहस स्वीकार किया है। जमीन जैर बहस का बेचान गलत रिकॉर्ड के आधार पर बिना कब्जे के हुआ है। जमीन जैर बहस के सम्बन्ध में राजस्व अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ की अदालत में बेचान की कार्यवाही होने के पहले से अपीलान्ट्स व रेस्पोजेन्ट सं० 1 के मध्य राजस्व वाद लम्बित है जिसकी जानकारी रेस्पोजेन्ट को रही है। उक्त राजस्व वाद की जानकारी अदालत मातहत को भी रही है। वास्तविक रूप से जमीन जैर बहस अनुसूचित जाति की खातेदारी की है और अदालत मातहत ने उक्त तमाम तथ्यों की जानकारी होते हुये भी रेस्पोजेन्ट सं० 2 के हक में नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। जमीन जैर बहस अपीलान्ट्स के कब्जे काश्त व खातेदारी की है। खातेदारी हककों एवं बेचान के पहले से कर रखा है। उक्त तथ्य की जानकारी पटवारी हल्का, भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार ( भू अभिलेख ) सूरजगढ को रही है। जमीन जैर बहस के गत खसरा नं० 213/2 रहे है जो पहले अपीलान्ट्स की माता की खातेदारी में रही है। इस प्रकार अपीलान्ट्स आदेश जैर बहस से प्रभावित है और प्रभावित पक्षकार की हैसियत से यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। इजाजत हेतु दफा 96 का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। रेस्पोजेन्ट सं० 1 ने गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर जमीन जैर बहस का बेचान दिनांक 19.06.2020 को रेस्पोजेन्ट सं० 2 के सगे भाई बिजेन्द्र सिंह व मुंशीराम पुत्र दरियासिंह, जाति जाट, निवासी लाडुन्दा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं के हक में किया। उक्त बेचान बिना कब्जे व बिना प्रतिफल के हुये। रेस्पोजेन्ट संख्या 2 के भाई बिजेन्द्र सिंह के हक में नामान्तरकरण संख्या 1251 दिनांक 25.06.2020 को स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध अपीलान्ट्स द्वारा अदालत हाजा के यहा एक अपील उनवानी मु० बाला वगै० बनाम बिमला देवी वगै० अपील संख्या 175/2020 प्रस्तुत की गई जो अपील अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 12.08.2021 के द्वारा स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 1251 ग्राम दूदवा दिनांक 25.06.2020 को निरस्त किया गया और अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ को यह निर्देश दिये गये कि उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ की अदालत में विचाराधीन वाद संख्या 178/2009 में निर्णय के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करे। अदालत हाजा द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना के कम में नामान्तरकरण संख्या 1251 को अदालत मातहत ने नामान्तरकरण संख्या 1357 दिनांक 10.09.2021 ग्राम दूदवा के द्वारा खारीज कर दिया। अदालत मातहत ने रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 19.06.2020 को अवैध राजस्व रिकार्ड के आधार पर मुंशीराम के हक में हुए बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1327 ग्राम दूदवा दिनांक 08.04.2021 को स्वीकार किया और उक्त नामान्तरकरण संख्या 1327 ग्राम दूदवा को आदेश दिनांक 13.06.2021 के द्वारा रिव्यू कर निरस्त कर दिया और


अदालत मातहत ने उक्त रिब्यू आदेश मे यह फाईडिंग दी कि जमीन जैर बहस अनुसूचित जाति की खातेदारी की है और उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ की अदालत मे प्रकरण लम्बित है। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने जानबूझकर बदनीयती से रेस्पोजेन्ट संख्या 2 से षडयन्त्र कर उपर वर्णित तमाम तथ्यों को छिपाकर गलत रिकार्ड के आधार पर 1/2 हिस्से की भूमि का बेचान दिनांक 23.03.2022 को रेस्पोजेन्ट संख्या 2 के हक मे कर दिया और उक्त बेचान के आधार पर दिनांक 20.05.2022 को अदालत मातहत ने रेस्पोजेन्ट संख्या 2 के हक मे नामान्तरकरण संख्या 1440 ग्राम दूदवा स्वीकृत कर दिया। पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक तथा तहसीलदार सूरजगढ ने अपने पदीय कर्तव्य का दुरुपयोग कर नामान्तरकरण संख्या 1327 ग्राम दूदवा आदेश दिनांक 10.06.2021 मे दर्ज फाईडिंग को नजर अंदाज कर उक्त नामान्तरकरण संख्या 1440 साजसी रूप से रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 को फायदा पहुंचाने की नीयत से स्वीकार किया है। पटवारी हल्का दूदवा तथा भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त पीपली व तहसीलदार सूरजगढ को उक्त तथ्य की बखूबी जानकारी रही है कि नामान्तरकरण संख्या 1440 ग्राम दूदवा मे उल्लेखित भूमि खसरा नम्बर 374 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की खातेदारी की भूमि रही है और उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे गलत रूप से दर्ज खातेदार रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने जमीन का बेचान दिनांक 19.06.2020 को रेस्पोजेन्ट सं० 2 के भाई बिजेन्द्र सिंह व मुशीराम नामक व्यक्ति को कर दिया है। जिनके हक मे क्रमशः नामान्तरकरण संख्या 1251 ग्राम दूदवा दिनांक 25.06.2020 व नामान्तरकरण संख्या 1327 ग्राम दूदवा दिनांक 08.04.2021 को स्वीकृत हो चुके है और उक्त दोनो नामान्तरकरण संख्या 1327 ग्राम दूदवा दिनांक 10.09.2021 व दिनांक 10.06.2021 के निरस्त किये जा चुके है। इसके बावजूद भी अवैध व शून्य बेचान के आधार पर राजस्व वाद लम्बित रहने के दौरान अदालत मातहत ने नामान्तरकरण जैर बहस स्वीकार किया है। राजस्व वाद की अदालत मातहत को जानकारी रही है। विधि मे यह व्यवस्था है कि राजस्व वाद लम्बित रहने के दौरान नामान्तरकरण की कार्यवाही किसी अन्य व्यक्ति के हक मे नहीं करनी चाहिए। विधि मे यह भी व्यवस्था है कि गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर हुए बेचान के आधार पर क्रेता के हक मे नामान्तरकरण स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अदालत मातहत ने अपने पद का दुरुपयोग कर जान बूझकर अवैधानिक कृत्य किया है। उपरोक्त अवैध राजस्व रिकार्ड व लम्बित दावा तथा पूर्व मे हुए बेचान एवं स्वीकृत हुए नामान्तरकरण तथा निरस्त हुए नामान्तरकरण आदेशों की जानकारी रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 को रही है। और इसके बावजूद भी रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने बिना हक अधिकार के रेस्पोजेन्ट संख्या 2 के हक मे बेचाननामा निष्पादित व पंजीबद्ध करवाया है और बाला-बाला रूप से रेस्पोजेन्ट संख्या 2 ने अपने हक मे नामान्तरकरण जैर बहस स्वीकार करवाकर अपीलान्ट व रेस्पोजेन्ट संख्या 3 को नुकसान कारित करने के उद्देश्य से रेस्पोजेन्ट संख्या 3 से ऋण प्राप्त कर रेस्पोजेन्ट संख्या 3 के नाम रहन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1443 दिनांक 25.05.2022 को स्वीकार करवा है जो कि एक अपराध है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। अपीलान्ट्स का वाद विषय वस्तु से संबंध है। इस तथ्य की जानकारी अदालत मातहत को आदेश जैर बहस पारित होने के रोज रही है। अपीलान्ट्स के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं हुई है। अदालत मातहत ने नामान्तरकरण संख्या 1327 ग्राम दूदवा रिब्यू आदेश दिनांक 10.06.2021 मे दी गई फाईडिंग को नजर अंदाज कर उसके विपरीत निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अदालत मातहत ने विधि की अवहेला कर अपने पद का दुरुपयोग किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2022 बाबत नामान्तरकरण सं० 1440 ग्राम दूदवा, तहसील सूरजगढ जमीन खसरा नं० 374 को अपास्त किये जाने का आदेश दिया जावे।

रेस्पोजेन्ट सं० 3 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। रेस्पोजेन्ट सं० 3 के विरुद्ध एकतरफा बहस सुनी गई।

बहस के दौरान वकील रेस्पोजेन्ट्स सं० 1 व 2 ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोजेन्ट सं० 1 बिमला देवी ने मुन्शीराम के पक्ष मे विवादित भूमि के क्रम मे किये गये बेचान पत्र का नामान्तरकरण निरस्त होने पर इसके बाद सूबेसिंह को बेचान किया है। सूबेसिंह के पक्ष मे भरा गया नामान्तरकरण सही है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के यहां विचाराधीन दावे मे जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार आगे नामान्तरकरण स्वीकृत या खारीज हो जावेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमि ग्राम दूदवा के खसरा नम्बर 374 के संबंध में खातेदारों के हक व अधिकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ में विचाराधीन दावे में तय होंगे। इसकी पुष्टि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, पीठ जयपुर द्वारा प्रकरण सं० निगरानी/एलआर/60/01/जयपुर उनवानी सीताराम व अन्य बनाम भैरू व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2006 से भी होती है। ऐसी स्थिति में हम अदालत मातहत द्वारा नामान्तरकरण सं० 1440 दिनांक 22.05.2022 वाले ग्राम दूदवा जमीन खसरा नं० 374 के क्रम में भरे गये नामान्तरकरण को उचित नहीं मानते हैं। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 22.05.2022 निरस्त किया जाता है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फ़ैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ़्तर हो।

आदेश आज दिनांक 09.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( एल०एस०कुडी )  
जिला कलक्टर  
जिला कलक्टर झुंझुनू